क्या सरकार उसके ऊपर जांच बैठाएगी, जांच करवाएगी, इसकी फैक्ट फाइंडिंग करवाएगी और बैगर्स होम में जो करप्शन है उसकी कोई जांच होती है या नहीं ? अगर नहीं होती है तो कैसे सरकार उसके ऊपर वाच ऐसी रखेगी, कैसे उसको अपने नियंत्रण में रखेगी ? इसके लिए सरकार के पास क्या मशीनरी है।

श्रीमती शीला कौल : देखिए, आपने अभी बताया है कि इस पर सरकार क्या वाच रखेगी, तो जरूर वाच रखेगी। जरूर वाच रखा जाएगा।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैंने कितनी मेहनत की है, उपाध्यक्ष महोदय, आप इसको हुश अप मत दीजिए। दो केसेज मैंने पकड़े हैं। दो केसेज मैंने छुड़वाए हैं। इनके सम्बन्ध में आप जांच करवाएंगी ? What about my question ?

Mr. DEPUTY-SPEAKER : Action will be taken on whatever you have said, and they will inquire into it.

श्री पी० के० थुंगन : आपने यह सवाल उठाया कि बैगर है या नहीं, आप की मशीनरी इसमें क्या करती है ? कोई मशीनरी इसके लिए है या नहीं ? उसके लिए तो मैं कहना चाहता हूं कि आपको कोर्ट के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के द्वारा यह तय होता है। हमारे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद कोर्ट कहता है कि यह सचमुच बैगर है या नहीं। जो बैगर नहीं है उसको छोड़ दिया जाता है।

SHRI RAM VILAS PASWAN : Where is the defence lawyer ? Is there any defence lawyer there.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is telling you the procedure. Should you not listen to him ?

SHRI P.K. THUNGON : About the two specific cases which you have mentioned, it has already been stated by my hon. senior colleague that we would look into their cases about Ram Vilas Paswan and Meghu Sada. So, we will get those cases looked into.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Will you inform the House after that ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Paswan, he said he would look into it and get a reply.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Who will reply ? Is it the Minister or the officials ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : You leave it to the Department. There is a procedure.

SHRI P.K. THUNGON : He knows it very well that when I say 'we will get them looked into', we will certainly inform. Are you happy now ?

(Interruptions)

13.20 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to check the growth of illegal and fake finanance and savings companies in the country.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल देश के विभिन्न भागों में, सेविंग्ज फाइनेन्स तथा चिटफंड कम्पनियों के नाम से अनेक अवैधानिक और फर्जी संस्थायें कार्य कर रही हैं। इनके कार्यालय शहरों से लेकर छोटे-छोटे

कस्बों तक में है। इन कम्पनियों का खुलना एक महामारी की तरह घातक सिद्ध हो रहा है, फिर भी अपनी पूंजी बढ़ाने के चक्कर में आम आदमी इन फर्जी कम्पनियों के चक्कर में पड़ जाता है और लुट जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि इन कम्पनियों द्वारा धन बढ़ाने का भारी प्रचार किया जाता है और लालचवश सीधे-सादे आदमी भारी संख्या में इनके खातेदार बन जाते हैं। जैसे ही पांच दस लाख रुपया किसी कम्पनी के पास जमा हुआ वैसे ही एक रात को उस कम्पनी के दफ्तर में ताले पड़ जाते हैं और उनके कार्यकर्ता जमापूंजी और कुर्सी मेज उठाकर फरार हो जाते हैं। बताया जाता है कि इन फर्जी कम्पनियों की पुलिस से भी मिली-भगत होती है। अभी कुछ दिन पहले आजमगढ़ में एक कम्पनी ने भी ऐसा ही किया।

(ii) Need to direct the Kendriya Vidyalaya Sangathan to take up construction on the plot allotted to them at Cuttack.

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (Cuttack) : Under Rule 377, I make the following statement.

The Government of Orissa has provided 5 acres of land to Kendriya Vidyalaya Sangathan for construction of central school building a Cuttack. Instead of starting construction on the site leased out to them, the sangathan has now come up with a requisition for allotment of additional 7 acres of land. The land already allotted to them inside the Barabati fort is a very valuable piece of land. It may not be possible to provide additional land by the State Government at this site. At present the central school at Cuttack has been functioning at the old circuit house. Apart from the fact that the old circuit house is very badly required for accommodation of the visitors and officers, the central school can hardly accommodate any further classes which will open from the next academic session in that building. The attitude of the sangathan has created discontentment among the people of the city. The central school has submitted an ultimatum to the effect that the admission to class I during 1984-85 will be stopped if the State Government do not provide more accommodation by 31st March, 1984. Unless the central school building is constructed, the fate of the students of the Cuttack central school will hang in the balance.

In view of this, I request the Minister of Education to direct the sangathan to take up the construction work on the plot allotted to them by the State Government forthwith.

(iii) Need to improve amenities in the Railway Colonies in Danapur.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, दानापुर पूर्व रेलवे का डिवीजन मुख्यालय है। यहां हजारों मजदूर काम करते हैं। रेलवे कर्मचारियों की अनेकों समस्यायें हैं जिनका समाधान निकालने की आवश्यकता है। एक बड़ी संख्या में रेल मजदूर क्वाटरों में रहते हैं। परन्तु, रेलवे कालोनियों की सफाई असंतोषजनक है। मच्छरों का साम्राज्य है। पानी निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। रेलवे अस्पताल की व्यवस्था भी असंतोषजनक है। आवश्यक दवाओं की कमी है। बेडों की संख्या और बढ़ाने की जरूरत है। मर्द और महिला डाक्टरों की भी कमी है। सभी कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं है। पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं है।

दानापुर के रेल कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वहां कोई केन्द्रीय